दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अक्तूबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **5**

- प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास 5
- पचमढ़ी में 'नीमघान एडवेंचर टूर' शुरू 5
- चिकित्सा मंत्री ने किया जनता क्लिनिक का शुभारंभ 6
- मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया मंडल का मोबाइल एप 6
- गांधी जयंती पर 'प्रशासन गाँवों के संग' एवं 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान की शुरुआत 7
- 'वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इको-सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' 7
- एससी एवं ओबीसी विकास कोष के गठन को मंजूरी 7
- प्रदेश की 30 पेयजल जाँच प्रयोगशालाओं को मिला 'एनएबीएल एक्रीडिशन' 8
- राज्य मानव अधिकार आयोग के त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन 9
- 'इन्वेस्ट राजस्थान-2022' 9
- श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर तक नये नेशनल हाईवे को मंजूरी 10
- सांभर झील प्रबंधन एजेंसी के गठन को मिली मंजूरी 10

नोट :

- 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ 11
- 33 ज़िलों में 'प्रतापगढ़' वैक्सीनेशन के मामले में बना नंबर-1 11
- मुख्यमंत्री ने विद्युत शुल्क संबंधी नियमों में संशोधन को दी मंज़ूरी 12
- मुख्य सचिव ने एम-पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया 12
- माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा एवं पिलानी को आरयूआईडीपी में जोड़ने की मंज़ूरी 13
- राष्ट्रीय अमृता हाट का उद्घाटन 13
- राजस्व दिवस 14
- 'रंग भरे गुब्बारे' 14
- ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे-स्टेट फैक्ट शीट कार्यशाला 14
- अंग्रेज़ी माध्यम में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ 15
- सौ फीसदी टीकाकरण 15
- कृमिनाशक दवा कार्यक्रम का शुभारंभ 16
- घर-घर औषधि योजना 16
- पंचायत चुनाव, 2021 17
- 7 ज़िलों के 3704 गाँव अभावग्रस्त घोषित 17

नोट :

दृष्टि
The Vision

नोट :

राजस्थान

प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 30 सितंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ एवं दौसा ज़िलों में स्थापित किये जाने वाले 4 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से बाकी बचे जालौर, राजसमंद और प्रतापगढ़ ज़िलों में भी राजकीय मेडिकल कॉलेज को शीघ्र मंज़ूरी देने का आग्रह किया।
- उन्होंने कहा कि राज्य के 33 में से 30 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज या तो संचालित हैं या फिर निर्माण की प्रक्रिया में हैं और वर्ष 2023 तक ये संचालन अवस्था में होंगे।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान में 16 मेडिकल कॉलेजों का निर्माणकार्य प्रक्रियाधीन है। 5 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे इन महाविद्यालयों की कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 2 हज़ार करोड़ रुपए) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
- ये कॉलेज सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और दौसा के अलावा अलवर, बूंदी, टोंक, झुंझुनूं, नागौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर में भी बन रहे हैं।
- वर्तमान में राज्य में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 2830 सीटें हैं। निर्माणाधीन सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के आरंभ होने के बाद एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 4 हज़ार से अधिक होने की संभावना है।

पचमढ़ी में 'नीमघान एडवेंचर टूर' शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 2 अक्टूबर, 2021 को पर्यटकों और एडवेंचर लवर्स के लिये पर्यटन विभाग ने वन विभाग के सहयोग से पचमढ़ी में नवाचार के रूप में 'नीमघान एडवेंचर टूर' की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- नीमघान एडवेंचर टूर सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व क्षेत्र में संचालित होगा। इसमें पर्यटक एडवेंचर टूर के दौरान वाइल्ड लाइफ, रॉक पेंटिंग, बटर फ्लाई पार्क, कॉफी गार्डन देखने के साथ लंच में कोदो-कुटकी, ज्वार और बाजरा से बने व्यंजनों का लुत्फ ले सकेंगे।
- नीमघान एडवेंचर टूर के लिये राज्य पर्यटन विकास निगम और सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व के बीच अनुबंध किया गया है।
- नीमघान एडवेंचर टूर रोजाना निगम की पचमढ़ी स्थित इकाइयों होटल ग्लेन व्यू और चंपक बंगले से सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त होगा। टूर में जंगल ट्रेल के अतिरिक्त जिप्सी के द्वारा भी भ्रमण कराया जाएगा। एक जिप्सी में अधिकतम 6 व्यक्ति बैठ सकेंगे।
- लगभग 30 किलोमीटर के दिनभर के एडवेंचर टूर में पर्यटकों को 500 मीटर की दूरी की एक जंगल ट्रेल भी कराई जाएगी। पर्यटकों के लिये निगम ने कुछ खास इंतजाम किये हैं, जिनमें दोपहर लंच में चूल्हे पर बनी रोटी, दोपहर में थोड़ी देर विश्राम करने के लिये खटिया और पेड़ों पर झूलों की व्यवस्था शामिल हैं।

नोट :

चिकित्सा मंत्री ने किया जनता क्लिनिक का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्टूबर, 2021 को चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने इसी कड़ी में वर्चुअल माध्यम से जालौर के लिये जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान में अब तक 12 जनता क्लीनिक जयपुर व 4 जोधपुर में खोले जा चुके हैं।
- डॉ. शर्मा ने अपने राजकीय आवास से जालौर के इंडस्ट्रीयल एरिया में जनता क्लिनिक को ऑनलाइन माध्यम से आमजन को समर्पित किया।
- उन्होंने बताया कि ग्रेनाइट एसोशिएशन के सहयोग से जनता क्लिनिक के लिये ज़मीन, भवन, एंबुलेंस, आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था की गई है।
- जनता क्लिनिक के प्रारंभ होने से इंडस्ट्रीयल एरिया और आसपास के क्षेत्रों के 20 से 25 हज़ार रहवासियों के लिये सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
- जनता क्लीनिक के माध्यम से आमजन को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ एवं परामर्श, एएनसी सेवाएँ, टीकाकरण सेवाएँ, परिवार कल्याण सेवाएँघ् एनसीडी स्क्रीनिंग सेवाएँ, नि:शुल्क जाँचें (प्राथमिक स्तर), नि:शुल्क दवा (प्राथमिक स्तर) आदि सहित लगभग 325 तरह की दवाएँ व 8 तरह की जाँचें नि:शुल्क करवाई जा सकेंगी।
- मुख्यमंत्री की वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के अरबन स्लम एरिया, सघन बस्तियों में राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में जनता क्लिनिक का संचालन किया जाना था, लेकिन कोविड जैसी महामारी के चलते यह कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही अब प्रदेश में जनता क्लिनिक चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया मंडल का मोबाइल एप

चर्चा में क्यों ?

- 2 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के शुभारंभ अवसर पर राजस्थान आवासन मंडल के मोबाइल एप RHB AWAS को भी लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान आवासन मंडल द्वारा राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के आवासों की आवश्यकता जानने के लिये डिमांड सर्वे करवाया जाएगा। आवास की आवश्यकता का पता लगने पर आवासन मंडल नगर निकायों से ज़मीन खरीद कर या आवंटित कराकर वहाँ योजनाएँ विकसित कर सकेगा।
- यह सर्वे मंडल द्वारा मोबाईल एप RHB AWAS के माध्यम से करवाया जाएगा।
- इस सर्वे में यूजर से यह जानकारी मांगी जाएगी कि उसे किस श्रेणी का आवास चाहिये, जैसे- 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके अथवा स्वतंत्र आवास। इसके बाद उसे एप में लागत भरनी होगी कि उसे कितनी लागत का आवास चाहिये जैसे 8 से 10 लाख रुपए तक का, 12 से 15 लाख रुपए तक का, 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का अथवा 30 से 40 लाख रुपए तक के मूल्य का। इसके बाद वह अपना शहर अंकित करेगा और अंत में सबमिट बटन दबा कर सर्वे को पूर्ण करेगा।
- इससे तीन बातें पता चलेंगी कि किस शहर के लोगों को किस आकार का और किस मूल्य का आवास चाहिये।
- स्वयं को रजिस्टर करें, स्वंतत्र आवास एवं फ्लैट का विकल्प का चयन करें, आवास के क्षेत्रफल का चयन करें और उसके बाद आवास की लागत का चयन कर सबमिट दबाकर सर्वे को पूर्ण करें।

नोट :

गांधी जयंती पर 'प्रशासन गाँवों के संग' एवं 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 2 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधीजी की जयंती के शुभ अवसर पर 'प्रशासन गाँवों के संग' एवं 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- अशोक गहलोत ने गांधी दर्शन म्यूजियम का शिलान्यास एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का लोकार्पण भी किया।
- गांधी दर्शन म्यूजियम सेंट्रल पार्क में बनेगा, जबकि कनक भवन में 1.07 करोड़ रुपए की लागत से बने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज में गांधीजी से जुड़े शोध कार्य होंगे।
- महात्मा गांधी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए प्रशासन एवं सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिये युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तथा पुणे स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज़ पर इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'प्रशासन गाँवों के संग' एवं 'शहरों के संग' अभियान की मार्गदर्शिका, सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित ई-बुकलेट तथा भवन विनियम कंपेडियम का विमोचन भी किया। साथ ही, राजस्थान आवासन मंडल के मोबाइल ऐप की लॉन्चिग एवं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी पंकज शर्मा को कार्ड वितरित किया।

'वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इको-सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट'

चर्चा में क्यों ?

- 1 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को मरुस्थलीय क्षेत्रों की वानिकी, वन्य जीव संरक्षण के साथ-साथ इससे संबंधित ज्ञानवर्द्धन और प्रशिक्षण देने के लिये ताल छापर में 'वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इको-सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इससे न केवल कार्मिकों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल सकेगी, बल्कि इससे वन्यजीवों और वनों के संरक्षण-संवर्द्धन में भी सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री द्वारा की गई वर्ष 2021-22 के बजट घोषणा की अनुपालना में ताल छापर में वाइल्ड लाइफ मैंनेजमेंट एंड डेजर्ट इको-सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत से स्टाफ को काले हिरण सहित अन्य वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्द्धन की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। साथ ही ग्रास लैंड, डेजर्ट इको-सिस्टम और उसके आसपास के क्षेत्रों के संबंध में भी स्टडी और ट्रेनिंग हो सकेगी।
- यह राजस्थान का चौथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें वन विभाग के स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग और ज्ञानवर्द्धन हेतु विभिन्न ट्रेनिंग करवाई जाएंगी।
- वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि पूरे विश्व में काले हिरणों के संरक्षण के लिये ताल छापर की प्रसिद्धि है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शुरू होने से यह मुहिम और आगे बढ़ेगी, जिससे वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्द्धन समुचित तरीके से हो सकेगा।

एससी एवं ओबीसी विकास कोष के गठन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 4 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति विकास कोष (Scheduled Castes Development Fund) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष (Other Backward Classes Development Fund) के गठन को मंज़ूरी दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस कोष से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये बने छात्रावासों का तथा आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, उनमें सुविधाओं के विकास, खेलकूद सामग्री एवं कंप्यूटर उपलब्ध कराने, इन वर्गों के युवाओं को रोज़गारपरक कार्यों हेतु औज़ार खरीदने के लिये 5 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य किये जाएंगे।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाल्मीकि समाज के बच्चों एवं युवाओं को आगे बढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से गठित वाल्मीकि कोष से 5 करोड़ 57 लाख रुपए व्यय करने को मंज़ूरी दी है।
- उल्लेखनीय है कि इससे वाल्मीकि समाज के छात्रावासों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सफाई के पेशे में लगे लोगों के बच्चों को मेरिट के आधार पर अतिरिक्त 5 हज़ार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता, रोज़गारपरक कार्यों हेतु औज़ार खरीदने के लिये 5 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य किये जाएंगे।

प्रदेश की 30 पेयजल जाँच प्रयोगशालाओं को मिला 'एनएबीएल एक्रीडिशन'

चर्चा में क्यों ?

- 5 अक्टूबर, 2021 को प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बताया कि राज्य के 30 ज़िलों के ज़िलास्तरीय पेयजल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाओं को 'एनएबीएल एक्रीडिशन' (नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज) मिला है, जबकि तीन ज़िलों को एक्रीडिशन मिलना शेष है।

प्रमुख बिंदु

- इन 30 ज़िलों में- अजमेर, अलवर, बाँसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूँगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर शामिल हैं। वहीं चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर एवं प्रतापगढ़ की प्रयोगशालाओं को एक्रीडिशन मिलना शेष है।
- जलदाय मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वीकृत परियोजनाओं में 'हर घर नल कनेक्शन' के माध्यम से स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति की मॉनीटरिंग के लिये प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिये 'फील्ड टेस्टिंग किट' उपलब्ध कराई गई है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग एंड सर्विलियंस (डब्ल्यूक्यूएमएस) के तहत वर्ष 2020-21 की वार्षिक योजना में 67 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य के 353 पंचायत समिति मुख्यालयों में से 102 में ब्लॉकस्तरीय पेयजल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- राज्य सरकार द्वारा जयपुर में मोबाइल जाँच प्रयोगशाला संचालित है, जिसके एनएबीएल 'रिकग्निशन' की कार्यवाही चल रही है। साथ ही जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के 20 अन्य ज़िलों में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेयजल गुणवत्ता जाँच के लिये संचालित मोबाइल प्रयोगशालाओं के एनएबीएल 'रिकग्निशन' की कार्यवाही भी प्रगति पर है।
- जलदाय मंत्री ने बताया कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के तहत जयपुर में राज्यस्तरीय प्रयोगशाला का नया भवन पानीपेच में बनाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि देश में एनएबीएल जाँच प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के लिये राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र संस्था है। इसके द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025 के तहत परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल प्रमाणीकरण दिया जाता है। यह संस्था भारत सरकार में 'क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया' के तहत स्थापित है, जो लेबोरेट्रीज के 'एनएबीएल एक्रीडिशन' के लिये 'परफॉर्मेंस ऑडिट' के बाद प्रमाणीकरण करती है।

नोट :

राज्य मानव अधिकार आयोग के त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 6 अक्तूबर, 2021 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास ने शासन सचिवालय स्थित आयोग कार्यालय में 'राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पत्रिका में आवश्यक आदेश एवं महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किये जाने के संबंध में तथा मानव अधिकार से संबंधित सूचनाओं के बारे में बताया जाएगा।
- पत्रिका के विमोचन के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया।
- आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने इस वेबसाइट के संबंध में कहा कि प्रदेश में दूर-दराज में रह रहे गरीब व्यक्ति अपने मामले/केस के संबंध में घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और परिवादियों को अपने केस में स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये जयपुर मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- गोयल ने बताया कि आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट (rshrc.rajasthan.gov.in) पर 12 अक्तूबर से ऑनलाइन सुविधा (case/complaint search) प्रारंभ की जा रही है, जिसका प्रयोग कर आयोग में दर्ज विभिन्न परिवादों से संबंधित विवरण और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- डिस्पोजल (खारिज) हुए मामलों से संबंधित आदेश (ऑर्डर) भी परिवादी/प्रार्थी स्वयं के स्तर घर बैठे डाउनलोड कर सकेगा।

'इन्वेस्ट राजस्थान-2022'

चर्चा में क्यों ?

- 6 अक्तूबर, 2021 को राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजस्थान को निवेश का हब बनाने एवं नए निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 20 एवं 21 जनवरी, 2022 को जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में स्टेट इन्वेस्टर समिट 'इन्वेस्ट राजस्थान 2022' का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सूत्रों के अनुसार इस समिट के दौरान निवेश संबंधी कार्य ऑन दी स्पॉट किये जाएँगे।
- समिट से पहले मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्रियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल देश एवं देश से बाहर के निवेशकों से संपर्क कर उन्हें राजस्थान के विकास में भागीदार बनने के लिये आमंत्रित करेंगे।
- निवेशकों से जुड़ने के लिये 21 अक्तूबर, 2021 से वर्चुअल वेबिनार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोड शो तथा विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स के साथ चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे। इनके माध्यम से राजस्थान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- समिट के सफल आयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा 12 से 18 नवंबर के बीच दुबई में होने वाले दुबई एक्सपो के साथ ही अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्राँस एवं यूनाइटेड किंगडम में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो तथा अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंगलुरू एवं हैदराबाद में भी रोड शो आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है।
- उल्लेखनीय है राजस्थान में पिछले ढाई साल में निवेशकों की सुविधा के लिये रिप्स-2019, सोलर एनर्जी पॉलिसी, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, एमएसएमई एक्ट जैसे नीतिगत निर्णय लेते हुए ईज ऑफ डूईंग बिज़नेस की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं।
- सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ इंवेस्टमेंट ने करीब 1 लाख 67 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को कस्टमाइज्ड इंसेंटिव देने की मंज़ूरी दी गई है। इन प्रस्तावों के साकार होने से प्रदेश में करीब 40 हज़ार नये रोज़गार पैदा होंगे। इनमें से 90 प्रतिशत रोज़गार प्रदेश के जालौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मिलेंगे।

नोट :

- अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पॉवर, ग्रीनको एनर्जीज एवं जेएसडब्ल्यू सोलर द्वारा प्रदेश में करीब 1 लाख 64 हज़ार 540 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 37 हज़ार रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- गौरतलब है कि भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में देश का नंबर वन राज्य बन गया है। विगत आठ माह में ही राजस्थान में 2348.47 मेगावाट नई सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है। इस अवधि में रिकॉर्ड 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है। राज्य में 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने में यहाँ उपलब्ध औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में प्रदेश में 350 औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ 84 हज़ार एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। आने वाले समय में 150 औद्योगिक पार्क और स्थापित किये जाएँगे। रीको क्षेत्र में 40 हज़ार ऑपरेशनल यूनिट स्थापित हैं।
- डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश के करीब 563 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा। 1730 किलोमीटर क्षेत्र में गैस ग्रिड प्रोजेक्ट होगा। प्रदेश में 3 विशेष आर्थिक ज़ोन (SEZ) स्थापित हैं।

श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर तक नये नेशनल हाईवे को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर के लिये नेशनल हाईवे को मंज़ूरी दे दी है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के महत्त्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट में श्रीगंगानगर के समीप साधुवाली से लेकर रायसिंहनगर के भोमपुरा तक 102 किलोमीटर लंबे एनएच-911 को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल हाईवे के अधिकारियों के अनुसार इसकी कार्यकारी एजेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) रहेगी। इससे पूर्व 'भारत माला प्रोजेक्ट' के इस एनएच-911 का रायसिंहनगर से रोजड़ी तक 98 किमी. का हिस्सा बन चुका है। साधुवाली से भोमपुरा तक निर्माण पूरा होने से 200 किलोमीटर सीमा पट्टी पूरी तरह से बेहतर सड़क सुविधा से जुड़ जाएगी।
- अधिकारियों के अनुसार हाईवे का निर्माण दो साल में पूरा किया जाएगा। यह नेशनल हाईवे 10 मीटर चौड़ा होगा। इस पर ट्रक व अन्य भारी मालवाहक वाहन 100 किमी. प्रति घंटा से ज़्यादा रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इस हाईवे पर 70 किमी. तक मौजूदा सड़क को ही चौड़ा किया जाएगा। बाकी 32 किमी. नई रोड़ बनेगी।
- गौरतलब है कि इस बॉर्डर एरिया में नेशनल हाईवे नहीं था। ज़िले में श्रीगंगानगर से राजियासर तक नेशनल हाईवे ही बड़े शहरों को जोड़ता है। एनएच-911 से बॉर्डर एरिया में रोड़ कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। भारी माल वाहक वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी साथ ही बॉर्डर एरिया के कस्बों में नये उद्योग पनपने की संभावना बनेगी।

सांभर झील प्रबंधन एजेंसी के गठन को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य सरकार ने सांभर झील के कुशल प्रबंधन के लिये समर्पित 'सांभर झील प्रबंधन एजेंसी' (Sambhar Lake Management Agency) के गठन को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- सांभर झील के प्रबंधन को सुदृढ़ और परिणामकेंद्रित करने के लिये पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर सांभर झील प्रबंधन हेतु गठित स्टैंडिंग कमेटी के अनुमोदन उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा सांभर झील की सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण विकास के लिये 'सांभर झील प्रबंधन एजेंसी' के गठन की अनुमति प्रदान की गई।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि जयपुर, अजमेर और नागौर ज़िलों में फैली सांभर झील अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त रामसर साइट है। यह झील भारत की दूसरी और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तथा एशिया का सबसे बड़ा अंतर-स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है।
- राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस मैनजमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। मैनेजमेंट एजेंसी सांभर झील क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिये कार्य करेगी।
- एजेंसी में खान, भू-जल एवं अभियांत्रिकी विभाग, वन एवं पर्यावरण, राजस्व, ऊर्जा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और नगरीय विकास विभाग के इंचार्ज सचिव होंगे।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, आरएजेयूवीएएस के निदेशक, सॉल्ट कमिश्नर निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर अजमेर नागौर के ज़िला कलेक्टर सदस्य सचिव होंगे।
- इसी तरह राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राज्य जैवविविधता बोर्ड और सांभर साल्ट लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक सदस्य होंगे।
- वर्तमान में राजस्थान में सांभर और भरतपुर के रूप में दो रामसर साइट्स चिह्नित हैं। राजस्थान के लिये यह इसलिये भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चिल्का, ई.के.डब्ल्यू. और लोकटक के बाद यह देश में चौथी ऐसी झील प्रबंधन एजेंसी होगी।

21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ

चर्चा में क्यों ?

- 13 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य में 'राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना' के अंतर्गत सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ दिये जाने का आदेश जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 में संशोधन करते हुए यह कदम उठाया गया है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व नि:शक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत वर्णित 7 प्रकार की श्रेणी के विशेष योग्यजन सहित 3 फीट 6 इंच ऊँचाई वाले बौनेपन वाले विशेष योग्यजनों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देय था।
- उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रभावी होने के कारण 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ मिल सकेंगे।

33 ज़िलों में 'प्रतापगढ़' वैक्सीनेशन के मामले में बना नंबर-1

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्यस्तर पर जारी ताजा रिपोर्ट में प्रतापगढ़ ज़िला कोविड वैक्सीनेशन में नंबर-1 बन गया है। प्रतापगढ़ ने 33 ज़िलों में वैक्सीनेशन के मामले में सभी ज़िलों को पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार प्रतापगढ़ ज़िले के 91.2 फीसदी लोगों ने प्रथम डोज व 48.6 प्रतिशत लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है। वहीं दूसरे स्थान पर सीकर व तीसरे पायदान पर हनुमानगढ़ ज़िला है।
- गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों से प्रतापगढ़ ज़िला राज्यस्तर पर आठवें स्थान पर चल रहा था, लेकिन पाँच दिवस के वैक्सीनेशन महाभियान में ज़िला प्रथम स्थान पर आ गया है।

नोट :

- कोविड-19 ऐप से डेटा का विश्लेषण करने से पता चला कि चिकित्सा विभाग की टीम ने हर घंटे 687 डोज लगाईं। पाँच दिन के महाभियान में टीमों ने 85 हज़ार से ज़्यादा की डोज लगाई।

मुख्यमंत्री ने विद्युत शुल्क संबंधी नियमों में संशोधन को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 13 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम-1970 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो आगामी 31 अक्टूबर से प्रभावी होगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व अर्जन विभागों में महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन करने की घोषणा की थी।
- इस क्रम में विद्युत शुल्क संबंधी प्रक्रियाओं को सरलीकृत कर ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं के उपयोग, उपभोग या अन्य को नि:शुल्क आपूर्ति के लिये कैप्टिव पावर प्लांट से ऊर्जा उत्पन्न करता है, वह विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा का लाभ ले सकेगा, जिससे व्यवहारी को विभागीय कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रस्तुत करने के तीन दिवस में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- इसके साथ ही तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर त्रैमासिक रिटर्न को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किये जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

मुख्य सचिव ने एम-पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्त्वावधान में एम-पासपोर्ट ऐप का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को ऐप से जोड़कर मैपिंग कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने एम-पासपोर्ट ऐप के बारे में बताया कि विदेश मंत्रालय तथा गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस ऐप में पुलिस सत्यापन के लिये अधिकतर सवालों का जवाब 'हाँ' या 'नहीं' में रिकॉर्ड किया जाता है।
- यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक है। इसके शुरू होने से पासपोर्ट के लिये पुलिस सत्यापन की अवधि दो सप्ताह से घटकर एक सप्ताह हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ जगहों पर 'पायलट रन' के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।
- विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में एम-पासपोर्ट ऐप के उपयोग से भारतीय नागरिकों के लिये पासपोर्ट प्राप्त करना तो आसान होगा ही, विदेश में रह रहे भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों के लिये 'पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट' प्राप्त करने में भी यह ऐप उपयोगी होगा।
- पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस सत्यापन में लगने वाले समय को कम करने के लिये कॉन्स्टेबल स्तर तक पुलिसकर्मियों का क्षमता संवर्द्धन किया जा रहा है। इस सुविधा से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में पुलिस की सेवा गुणवत्ता में सुधार आएगा।

नोट :

माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा एवं पिलानी को आरयूआईडीपी में जोड़ने की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा एवं पिलानी को राजस्थान सैकेंडरी टाउंस डवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट (आरएसटीडीएसपी) के तहत आरयूआईडीपी के फेज-4 के ट्रेंच-2 में जोड़ने के लिये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित आरयूआईडीपी फेज-4-ट्रेंच-2 में जोड़े गए इन चारों शहरों में विभिन्न प्रकार के विकास एवं सौंदर्यकरण के कार्य होंगे। इन विकास कार्यों से इन क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचा मज़बूत होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- प्रस्ताव के तहत नाथद्वारा शहर में 80 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति, सड़क सुदृढ़ीकरण एवं शहर के दो तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य किये जाएंगे। साथ ही माउंट आबू, पुष्कर तथा पिलानी शहर में भी 25-25 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास, शहरी सौंदर्यकरण एवं अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि आरयूआईडीपी के फेज-4 में 14 शहरों में सैनिटेशन, ड्रेनेज, पेयजल आपूर्ति एवं पर्यटन स्थलों के सौंदर्यकरण से संबंधित कार्य पहले से ही चल रहे हैं।
- चार नए शहरों के जुड़ने के बाद इन शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं शहर के सौंदर्यकरण के संबंध में प्रस्तावित कार्यों की डीपीआर संबंधित नगरीय निकायों द्वारा तैयार की जाएगी।

राष्ट्रीय अमृता हाट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 15 अक्तूबर, 2021 को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री के लिये बाज़ार उपलब्ध कराने हेतु जयपुर में जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 'राष्ट्रीय अमृता हाट' का उद्घाटन किया तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की ओर से तैयार किये गए जागरूकता रथों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अमृता हाट से इन महिलाओं की मेहनत और हुनर को बढ़ावा मिलेगा तथा इन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
- उन्होंने कहा कि त्योहारी मौसम में यहाँ से घरेलू आवश्यकताओं के सामान एवं हस्तनिर्मित सज़ावटी और कलात्मक व गुणवत्तापूर्ण सामान की खरीदारी की जा सकती है।
- अमृता हाट में कशीदाकारी, लाख की चूड़ियाँ, पेपरमेशी आइटम, सलवार-सूट, टेराकोटा, कश्मीरी ऊनी शॉल, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, चिकन एवं ज्वैलरी वर्क, काँच एवं पेच वर्क, सभी प्रकार के आचार, मुरब्बा, मसाले एवं अन्य हस्तनिर्मित आकर्षक उत्पाद ग्राहकों को वाज़िब दाम में उपलब्ध हैं।
- उल्लेखनीय है कि जयपुरवासियों के लिये एक ही जगह विभिन्न स्थानों के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री के उद्देश्य से शिल्पग्राम में राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन 15 से 24 अक्तूबर, 2021 तक किया जा रहा है।
- इस हाट में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 140 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में आगंतुकों का प्रवेश नि:शुल्क है। मेला परिसर में आगंतुकों के लिये अनेक लजीज व्यंजन भी बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

नोट :

राजस्व दिवस

चर्चा में क्यों ?

- 15 अक्तूबर, 2021 को राजस्थान राजस्व विभाग द्वारा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में राजस्व दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्व दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व विभाग के जयपुर ज़िले के कार्मिकों- किशनगढ़ रेनवाल तहसीलदार सुमन चौधरी, सांगानेर नायब तहसीलदार नीरु सिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक गोपाल सिंह और पटवारी राजेंद्र सिंह गुर्जर को सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में 28 फरवरी, 2020 को राजस्व विभाग की बजट अनुदान मांगों पर अपने भाषण के दौरान राज्य में 15 अक्तूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- गौरतलब है कि 15 अक्तूबर, 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, जिससे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार संभव हुए थे।

'रंग भरे गुब्बारे'

चर्चा में क्यों ?

- 16 से 18 अक्तूबर, 2021 तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र की सुरेख आर्ट गैलरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी शुचि शर्मा की चित्रकला प्रदर्शनी 'रंग भरे गुब्बारे' का प्रदर्शन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ तथा राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने किया।
- इस चित्र प्रदर्शनी में शुचि शर्मा के जलरंगों से बने पॉर्ट्रेट, लैंड्स्केप्स, स्टिल लाइफ व अन्य जीवन से प्रभावित चित्रों का प्रदर्शन किया गया।
- शुचि शर्मा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में उन्होंने 120 से अधिक चित्र बनाये हैं, जिन्हें यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों से होने वाली आय ऐसे बच्चों के सहायतार्थ खर्च की जाएगी, जो कोविड महामारी के कारण अनाथ हो गए हैं।

ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे-स्टेट फैक्ट शीट कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

- 18 अक्तूबर, 2021 को राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे के अनुसार प्रदेश के 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत 4.1 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 8.5 प्रतिशत से बेहतर है।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे-स्टेट फैक्ट शीट रिलीज कार्यशाला के दौरान कहा कि राज्य सरकार की जन-घोषणा में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार राज्य में तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों की प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है कि स्टेट फैक्ट शीट में प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हैं।
- डॉ. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं में नशे की लत रोकने के लिये राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन को 30 मई, 2019 से प्रतिबंधित किया है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया गया।

नोट :

- उन्होंने बताया कि राज्य में हुक्का बार संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हुक्का बार संचालन प्रतिबंध के नियमों के उल्लंघन पर 1 से 3 लाख रुपए का जुर्माना तथा 6 महीने से 1 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है।
- चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 'निरोगी राजस्थान' अभियान के तहत भी प्रत्येक राजस्व गाँव में एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र, जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हों, का चयन किया था। कुल 94 हज़ार स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर ग्रामस्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों के प्रचार-प्रसार का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें नशामुक्ति एवं तंबाकू नियंत्रण को भी प्रमुखता से शामिल किया गया।
- कार्यशाला में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई के प्रोफेसर मुरलीधरण ने बताया कि सर्वे में प्रदेश की 34 स्कूलों के 2 हज़ार 735 बच्चों से विभिन्न सवाल पूछे गए थे। सर्वे के अनुसार 90 फीसद बच्चों ने माना कि तंबाकू सेवन की आदत सबसे पहले स्कूल से ही पड़ी। शहरों की बजाय गाँवों के बच्चों में तंबाकू सेवन की आदत ज़्यादा देखी गई। उन्होंने बताया कि इस आयु वर्ग की लड़कियों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत नहीं के समान है।

अंग्रेज़ी माध्यम में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ

चर्चा में क्यों ?

- 23 अक्तूबर, 2021 को प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किये जाने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में प्रथम चरण में 33 ज़िला मुख्यालयों पर संचालित महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में इसी सत्र से पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ शुरू की जाएंगी। शीघ्र ही ब्लॉक स्तर पर भी इसका विस्तार किया जाएगा।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक खंड में विद्यार्थियों की संख्या 25 होगी।
- इन कक्षाओं के लिये विद्यालयों हेतु शिक्षकों का चयन वर्तमान में कार्यरत् लेवल 1 अध्यापकों में से वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा।
- डोटासरा ने कहा की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरएससीईआरटी द्वारा विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। ये कक्षाएँ प्रतिदिन 4 घंटे तथा सप्ताह में पाँच दिन संचालित होगी।
- उन्होंने बताया कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों के वर्तमान भवन में किया जाएगा। अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होने पर विद्यालयवार अलग से भवन निर्माण किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग के इस आदेश के क्रियान्वयन के साथ राजस्थान अंग्रेज़ी माध्यम में राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन करने वाला वर्तमान में देश का एकमात्र राज्य बन गया है।

सौ फीसदी टीकाकरण

चर्चा में क्यों ?

- 23 अक्तूबर, 2021 को चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि प्रतापगढ़ प्रदेश का ऐसा ज़िला बन गया है, जहाँ कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज़ शत-प्रतिशत लोगों को लगाई जा चुकी है।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रतापगढ़ ज़िले को राज्यस्तर से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले 6 लाख 52 हज़ार 61 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिये लक्ष्य दिया गया था। इसके एवज में ज़िले में शनिवार को 6 लाख 52 हज़ार 869 लोगों को प्रथम डोज़ लगाई गई। इस प्रकार ज़िले में अब प्रथम और द्वितीय डोज़ लगवाने वाले लोगों की संख्या 9 लाख 71 हज़ार 841 हो गई है।

नोट :

- प्रदेश में 16 जनवरी, 2021 को पहली बार हेल्थवर्कर/फ्रंटलाइन वर्कर को टीके लगाने का कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद 1 मार्च, 2021 से 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए जाने शुरू हुए। 1 अप्रैल, 2021 को 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ और 10 मई, 2021 को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों का टीकाकरण वृहत् स्तर पर शुरू किया गया।
- आरसीएचओ डॉ. दीपक मीणा ने बताया कि महाभियान के लिये चिकित्सा विभाग की टीमों ने खतरों के बीच दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचकर टीकाकरण अभियान चलाया। बारिश और नदी में नाव के माध्यम से टीकाकरण कर्मी लोगों तक पहुँचे और टीके लगाए।

कृमिनाशक दवा कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 25 अक्तूबर, 2021 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने अजमेर के केकड़ी कस्बे से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कृमिनाशक दवा बच्चों को खिलाकर राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को आगामी 25 से 30 अक्तूबर तक कृमिनाशक एल्बेंडाजॉल दवा खिलाई जाएगी।
- यह कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश भर में 25 से 30 अक्तूबर तक संचालित होगा।
- उल्लेखनीय है कि कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण स्तर और बौद्धिक विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह कृमि बच्चों के पेट में पलने वाले कीड़े होते हैं। ये बच्चों के विकास को हर प्रकार से प्रभावित करते हैं।
- कृमि के पैलाव को निश्चित समयांतराल पर कृमि मुक्त (डिवार्मिंग) कर रोका जा सकता है। इसके लिये कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जाएगी।
- एल्बेंडाजॉल की गोली बच्चों और किशोर-किशोरियों को कृमिमुक्त रखने के लिये राष्ट्रीय कृमिमुक्ति कार्यक्रम के दौरान राज्य के सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर खिलाई जाएगी। इसमें एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की अहम भूमिका होगी।
- इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी इस पोस्टर के माध्यम से आमजन को पेट के कीड़ों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इनसे बचने के उपाय की जानकारी दी जाएगी। साथ ही नियमित अंतराल पर एल्बेंडाजॉल की खुराक लेकर कृमियों के जीवन चक्र को तोड़ने का आह्वान किया जाएगा।

घर-घर औषधि योजना

चर्चा में क्यों ?

- 25 अक्तूबर, 2021 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुनीश कुमार गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार एवं वन विभाग की महत्त्वपूर्ण घर-घर औषधि योजना के प्रथम वर्ष के पौधे वितरण कार्य में उदयपुर संभाग अव्वल रहा है। इसने शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

प्रमुख बिंदु

- मुनीश कुमार गर्ग ने बताया कि घर-घर औषधि योजना के पौध वितरण में उदयपुर संभाग के सभी ज़िलों में 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि दर्ज की गई है।
- बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और उदयपुर नॉर्थ ने आवंटित लक्ष्य के अनुरूप औषधीय वितरित किये हैं।

नोट :

- भरतपुर संभाग ने 81 प्रतिशत और अजमेर संभाग ने 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य अर्जित किया। जयपुर संभाग ने 76 प्रतिशत और कोटा संभाग द्वारा 74 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया। कुल मिलाकर राज्य में 50 लाख किट्स वितरित की गई हैं। यह वर्तमान वर्ष के कुल लक्ष्य का लगभग 80 प्रतिशत है।
- उल्लेखनीय है कि घर-घर औषधि योजना की घोषणा राजस्थान बजट 2021-22 में की गई थी। इस योजना के तहत 5 जुलाई, 2021 से पौधों का वितरण प्रारंभ हुआ। राजस्थान वन-विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

पंचायत चुनाव, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 26 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान के अलवर और धौलपुर ज़िलों में पंचायत समिति सदस्य एवं ज़िला परिषद सदस्य के लिये तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में 65.23 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य निर्वाचन आयुक्त पी.एस. मेहरा ने बताया कि तीसरे और अंतिम चरण में प्रदेश के अलवर एवं धौलपुर ज़िले की 7 पंचायत समितियों के 167 वार्डों एवं उनसे संबंधित ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिये मतदान हुआ।
- इस चरण में सर्वाधिक मतदान अलवर ज़िले की किशनगढ़ बास पंचायत समिति में हुआ, जहाँ 69.98 फीसद मतदाताओं ने वोट डाले।
- पंचायत समिति सदस्यों के लिये 606 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दोनों ज़िलों को मिलाकर कुल 7 लाख 76 हज़ार 284 मतदाता थे, जिनमें से 5 लाख 6 हज़ार 350 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
- उल्लेखनीय है कि 20 अक्टूबर, 2021 को पहले चरण में 64.24 फीसद मतदान हुआ था तथा 23 अक्टूबर, 2021 को दूसरे चरण में 57.46 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था।
- उपर्युक्त तीनों चरणों की मतगणना 29 अक्टूबर, 2021 को दोनों ज़िला मुख्यालयों पर करवाई जाएगी। वहीं पंचायतों के प्रमुख और प्रधान का चुनाव 30 अक्टूबर, 2021 व उप-प्रमुख व उप-प्रधान का चुनाव 31 अक्टूबर, 2021 को करवाया जाएगा।

7 ज़िलों के 3704 गाँव अभावग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों ?

- 26 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान राज्य सरकार ने इस वर्ष मानसून की बारिश में जलजमाव एवं बाढ़ आदि से खरीफ की फसल खराब होने के कारण प्रदेश के 7 ज़िलों के 3704 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इसके लिये आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- अधिसूचना के अनुसार, खरीफ फसल 2021 के लिये विभिन्न ज़िलों में की गई विशेष गिरदावरी के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के तहत इन गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
- इस अधिसूचना में बारां ज़िले में सर्वाधिक 1236 गाँव, झालावाड़ में 1177, कोटा में 485, बूंदी में 469 तथा टोंक ज़िले में 224 गाँव अभावग्रस्त घोषित किये गए हैं। धौलपुर और सवाईमाधोपुर ज़िलों में भी क्रमश: 72 और 41 गाँव अभावग्रस्त घोषित किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग ने 6 अगस्त, 2021 को राज्य के सभी ज़िलों में विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश जारी किये थे, जिसके रिपोर्ट में धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा एवं बारां के 3704 गाँवों की खरीफ फसलों में 33% से अधिक खराबी पाई गई थी।

नोट :